

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 701

दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

पीएम-जनमन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र

701. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आंध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की वर्षवार और जिलावार स्थिति क्या है;
- (ग) क्या पीएम-जनमन के अंतर्गत किसी भी परियोजना के समय और लागत में वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ख) : जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये की दर से कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृत और निर्मित किया जाना है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम जनमन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य	जिला	2023-24 में निर्माण के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	2024-25 में निर्माण के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल
आंध्र प्रदेश	एसआर	105	95	266
	विजियाना-गरम		1	
	मन्याम	29		
	प्रकाशम	1		
	श्रीकाकुलम	35		

(ग) से (घ) जैसा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, पीएम जनमन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलंब अथवा लागत वृद्धि का मामला उनके संज्ञान में नहीं लाया गया है।
